











# अल्पसंख्यक के नाम पर राजनीति ज्यादा खतरनाक

वाशष्ट भारताय समुदाया का सास्कृतक रूप से वावध पहचान का कवल  
अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करके ही बरकरार रखा जा सकता है।  
भारतीय सामाजिक प्रथाओं में प्रत्येक संस्कृति और धर्म के प्रति सहिष्णु और सर्व  
समावेशी रवैया शामिल है। भेदभाव, जबरन आत्मसातीकरण एवं धर्म-परिवर्तन  
समुदायों को खतरे में डालता है और भारतीय समाज के समग्र सार एवं उसके मूल  
स्वरूप को प्रभावित करता है। भेदभाव नफरत का सबसे खराब एवं वीभत्स रूप है।  
लोगों के एक समूह के खिलाफ उनकी भाषाई या सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर  
हिंसक कार्रवाई करना किसी व्यक्ति के विवेक के लिए हानिकारक है।



लेखक

पहला बार 18 दिसंबर  
1992 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा  
अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों  
की रक्षा, राष्ट्र निर्माण में योगदान के  
रूप में चिह्नित कर अल्पसंख्यकों  
के क्षेत्र विशेष में ही उनकी भाषा,  
जाति, धर्म, संस्कृति, परंपरा आदि  
की सुरक्षा को सुनिश्चित करने एवं  
समाज को जागृत करने हेतु मनाया  
जाता है। इस साल थीम ह्याविविधता  
और समावेश का जशन मनानाल्ह है।  
इसका उद्देश्य भारत के अल्पसंख्यकों  
की समावेशिता और विविधता को  
बढ़ावा देना है। यह थीम इस बात  
पर जोर देती है कि अल्पसंख्यकों  
अधिकार सिर्फ़ आकांक्षाएं नहीं हैं  
बल्कि बेहतर भविष्य के लिए लोगों  
और समुदायों को सशक्त बनाने का  
एक व्यावहारिक तरीका भी हैं। संयुक्त  
राष्ट्र ने अल्पसंख्यकों की परिभाषा  
दी है कि ऐसा समुदाय जिसका  
सामाजिक, अर्थिक तथा राजनीतिक  
रूप से कोई प्रभाव न हो और जिसका  
आबादी नगण्य हो, उसे अल्पसंख्यक  
कहा जाएगा। भारत में, इस दिन राष्ट्रीय  
अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम)

दिवस व्यापक स्तर पर मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्रीय या जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों की धोषणा को जीवंतता प्रदान करने का दिवस है। भारत में केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के गैर-भेदभाव और समानता के अधिकारों की गारंटी के प्रयास सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध है। इस दिन, देश के अल्पसंख्यक समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों और मुद्दों पर ध्यान खींचा जाता है। लोग धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई और जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की बात करते हैं। भारत ह्यलोकतंत्र की जननीलक हलाता है, यहां के लोकतंत्र को खुबसूती प्रदान करने के लिये भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है और भाषाई, जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई उपक्रम एवं प्रयोग करता है। सरकार उन लोगों का गंभीरता एवं समानता से ख्याल रखती है जो अनुसूचित जनजाति

नकनका जात, सर्स्कृत अंतर सुमुद्रव व  
वावजूद आर्थिक या सामाजिक रूप  
वें विचित लोग हैं। इसमें कोई सदै  
हीं है कि प्रत्येक राष्ट्र में अलग-  
भलग जातीय, भाषाई और धार्मिक  
भल्पसंख्यक समूह होते हैं। भारत  
भनेक अल्पसंख्यक समुदाय है। आं  
देश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़  
देल्ली, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र  
ध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान  
मिलनाडु, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश  
और पश्चिम बंगाल जैसे विभिन्न  
ज्यों ने अपने-अपने राज्यों में राज  
भल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कर्त  
तों संविधान और संसद और राज  
विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित  
कानूनों में दिए गए अल्पसंख्यक  
हितों की रक्षा और संरक्षण कर  
ते। अल्पसंख्यक अधिकार दिवकर  
भल्पसंख्यकों के खिलाफ सभी  
काकर के भेदभाव को खत्म करने वे  
कसद से मनाया जाता है। हालांकि  
कानूनी रूप से भारत के संविधान  
भल्पसंख्यक की कोई स्पष्ट परिभासा  
हीं है लेकिन अल्पसंख्यकों वे  
हितों की रक्षा के लिए संविधान वे

A graphic illustration featuring three raised, clenched fists in red and white stripes, symbolizing protest or revolution. The fists are positioned in front of a stylized Earth globe against a blue background.

अल्पसंख्यक वर्ग का समालित करना का भाव है, मोदी सरकार ने अपने नए नारे के साथ ये एहसास दिलाया कि प्रयास किया है कि अल्पसंख्यक समुदाय का भी विश्वास अर्जित करेंगे। भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं तीन तलाक के विरुद्ध कानून लावा अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को बहुसंख्यक समाज के महिला बराबर बताने की कोशिश ऐसा प्रयास है। भारत की माटी ने ह्वासुधेर कुटुम्बक महल का उद्घोष करके सप्राणियों के सुखी एवं समृद्ध होने वाला कामना की है। यहां अल्पसंख्यकों साथ इसी उद्घोष की भाँति उदात्त बरती जाती है। महात्मा गांधी ने कभी है कि किसी राष्ट्र की महानाता इस बात से मापी जाती है कि वह अपने सबसे कमज़ोर नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। छँइस है से आजादी के बाद की सभी सरकारें ने अल्पसंख्यकों के साथ उदात्त प्रयत्न कल्याणकारी दृष्टिकोण अपनाया है। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों अपने स्वार्थों के लिये अल्पसंख्यकों को गुमराह किया है, साम्रदायिक

के लाकत्रिपर लाल और काल धब्बे लगते गये हैं। इन्हीं संकीर्ण एवं साम्प्रदायिकता की राजनीति करने वाले दलों ने अल्पसंख्यकों के कल्याण की बजाय उनको बोट बैंक मानकर उनके वास्तविक अधिकारों की अनदेखी की है। ऐसे राजनेताओं ने अल्पसंख्यकों का जीवन खतरे में है, कहकर उन्हें उकसाया है, राष्ट्र की मूलधारा से अलग-थलग करने की कौशिश की है, लेकिन मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण की अनेक बहुआयामी योजनाओं एवं नीतियों को लागू कर इन तथाकथित नेताओं की जुबान पर ताला लगा दिया है। सच कहा जाये तो देश में अल्पसंख्यक खतरे में नहीं हैं, अल्पसंख्यकों के नाम पर राजनीति करने वाले खतरे में हैं। भारत विविध संस्कृतियों और समुदायों का देश है, यही इसका सौनर्दद्य है। एक या अधिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव और जबरन आत्मसात करने से समृद्ध और ऐतिहासिक संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों का नुकसान हो सकता है जिन्होंने सदियों से भारत में अपनी विरासत संभाली है।

हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि पहले राहुल गांधी ने भाजपा की सरकार को सविधान के मद्दे पर अपने पाले में खींचा और अब फिलिस्तीन के

मुद्दे पर प्रियका वाडा ने महज एक झाला लटकाकर भाजपा और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को कठघेरे में खड़ा कर दिया है। संविधान के मुद्दे पर तेज़ प्रधानमंत्री जी लोकसभा में एक भाषण देकर फाइग हो गए लेकिन फिलिस्तीन के मुद्दे पर अभी तक सरकार ने चुप्पी साध रखी है।



झोला ढो रहा है। उन्होंने कहा—  
तुष्टिकरण की वजह से उन्हें (कानपुर में) देखा गया था।

मुद्दे मिल रहे हैं जिनके बारे में लिखने में मुझे तकलीफ होती है। आज मैं फिर उस गैर जरूरी मुद्दे पर लिख रहा हूँ उसके बारे में लोकसभा का कीमती वक्त तो अभी बर्बाद नहीं हुआ लेकिन भाजपा का कीमती वक्त जरूर बर्बाद हो गया। मुझे था कांग्रेस संसद प्रियंका वाड़ा का झोला। जी हाँ झोला। हमारी प्रियंका भाजपा के पास किसानों के मुद्दे पर बहस के लिए वक्त नहीं है लेकिन प्रियंका के झोले को लेकर पूरी सरकारी पार्टी बहस में उलझ गयी। किसा यह है कि प्रियंका वाड़ा लोकसभा में जो झोला लटका कर गयी उसके ऊपर फिलिस्तीन अंकित था और फिलिस्तीन का खरबूजा वाला ध्वज भी। बस यही भाजपा को खटक गया। इस कदम की भाजपा ने आलोचना की और उनके इस कदम को तुष्टिकरण करारा दिया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, गांधी परिवार तुष्टिकरण का

की गयी ज्ञाले की आलोचना के बाद प्रियंका भी कहाँ चुप रहने वाली थीं। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि यह आलोचना पितृसत्ता है, जहां उन्हें बताया जा रहा है कि क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। उन्होंने कहा, मैं पितृसत्ता का समर्थन नहीं करती। मैं वही पहननुग्री जो मैं चाहती हूँ। आपको याद होगा की इससे पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री भाई किरण रिजिजु प्रियंका के भाई राहुल गांधी की टीशर्ट पर आपति कर चुके हैं। वे कह चुके हैं कि राहुल टीशर्ट पहनकर संसद का अनादर करते हैं। दरअसल भाजपा राहुल गांधी से तो पहले से डरी हुई थी और अब प्रियंका के लोकसभा में आने के बाद भाजपा का डर दोगुना हो गया है। तभी तो कभी भाजपा को राहुल के टीशर्ट के बाहर झांकते टोले परेशान करते हैं तो कभी प्रियंका के कंधे पर लटका ज्ञाला। सर्विंद पात्रा के बाद भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित

अंत में, कांग्रेस में सभी के लिए नेटरन का भौम रहे, जो मानते थे कि प्रयंका का बाड़ा लंबे समय से प्रतीक्षित है। अपनामाधान थीं, उन्हें पहले ही इसे अपना नेना चाहिए था। वह राहुल गांधी की बड़ी आपदा है, जो सूचते हैं कि अंसंद में फिलस्तीन के समर्थन में बैठक चलना पिरुसता से लड़ाना है। यह सही है। मुसलमानों को सांप्रदायिक गणुओं का पैगाम देना अब पिरुसता के खिलाफ रुख के रूप में सार्वजनिक हो चुका है। कोई गलती न करें, कांग्रेस न फिलस्तीनी लीग है। आपको याद हो या न किन्तु मैं बता दूँ कि पिछले सप्ताह ईरानी दिल्ली स्थित फलस्तीनी दूतावास ने चार्ज़ डिअफेवर्स ने प्रियंका गांधी को बुलाकात कर उन्हें बायनाड से सांसद नवाचारित होने पर बर्धाइ भी दी थी। वर्व में कांग्रेस नेता गजा में इसराइल की अम्भारी की निंदा भी कर चुकी है। आजपा के ही सांसद अनुराग ठाकुर ने पहले कभी केंद्र में मंत्री होते ही

में लगी रहती हैं। उन्होंने बांग्लादेश में हिन्दुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में तो कुछ नहीं बोला। भाजपा के तमाम छोटे-बड़े नेता प्रियंका के झोले को लेकर प्रियंका को कोस रहे हैं। दरअसल प्रियंका के झोले ने भारत सरकार को फिलस्तीन के मामले में कठघरे में ला खड़ा किया है। भारत सरकार अभी तक ये तय नहीं कर पायी है कि वो भारत के पुराने मित्र फिलस्तीन के साथ है या इजराइल के साथ? फिलस्तीन के मामले में नेहरू और इंदिरा गांधी के युग में जो नीति थी उसे अटल जी के युग में भी दोहराया गया, लेकिन मोदी युग में फिलस्तीन को लेकर भारत की नीति अचानक बदल गय। भारत अब फिलस्तीनियों के संघर्ष और उनके मानवीय अधिकारों का दमन करने वाले इजराइल के साथ खड़ा है। भारत ने इजराइल के फेर में फिलस्तीन को एकदम भुला दिया है क्योंकि

प्रियंका बाड़ा ने एक झोले के जरिये फिलिस्तीन मुद्दे को जिस ढंग से उठाया है उसके बारे में आज नहीं तो कल संसद में भी बहस हो। संसद में बहस हो या न हो लेकिन संसद के बाहर तो ये बहस शुरू हो गयी है। बहस इस बात पर भी हो रही है कि क्या अब विपक्षी सांसदों को भाजपा यानि भाजपा सरकार से पूछाना होगा कि वे कौन से कपड़े पाहणकर संसद में आएं और कौन से कपड़े न पहने? कौन सा झोला लटकाएं और कौन सा नहीं? आपको याद होगा कि भाजपा पहले भी लोगों के खान-पान और पहनावे को लेकर सवाल खड़े करती रही है। कभी उसके निशाने पर हिजाब रहता है तो कभी हलाल और गैर हलाल किया हुआ भोजन। असम में भाजपा की डबल ईंजिन की सरकार होटलों में गौमांस बेचने पर प्रतिबन्ध लगा चुकी है लेकिन देश से गौमांस बाहर भेजने पार कोई भाजपा और उसके सहयोगी हिजाब पर तेजाबी रुख अखिलयार कार चुके हैं। लेकिन किसानों, मजदूरों के मुद्दे पर भाजपा का कोई प्रवक्ता, कोई नेता या संसद अपना मुंह नहीं खोलता। राहुल की टीशर्ट और प्रियंका के झोले से बौखलाई भाजपा का डर लोकसभा में इस जोड़ी की वजह से दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है। भाजपा ने राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में अपनी तामात ताकत झाँक दी थी लेकिन आम चुनाव में राहुल की अगुवाई में विपक्षी गठबंधन ने जो शानदार कामयाबी हासिल की थी उसे कोई भूला नहीं है। अब प्रियंका के लोकसभा में आने के बाद भाजपा को भय है कि कहीं प्रियंका भाजपा को बेनकाब करने में राहुल से भी आगे न निकल जाएँ, इसलिए अब भाजपा प्रियंका के पहनावे के साथ ही उनके झोले पर भी निगाह रखने लगी है।

जाते हैं जिससे

हताश होकर एक नए रास्ते पर चलना लगते हैं। हालात कैसे भी हों लेकिन बिना सोचे समझे उठाया हुआ कदम नुकसान पहुंचाता है। आज हमारे देश का विषय बहुत हताश और निराश है चाका है। पिछले दस सालों से वो मोर्ते से लड़ रहा है लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ पाया है। 4 जून को जलोक्सभा के चुनाव परिणाम आये तो विषय में खुशी की लहर दौड़ गई थी क्योंकि भाजपा को अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं मिला था। भाजपा बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई थीं विषय को लगा कि अब मोदी का प्रधानमंत्री बनना मुश्किल है क्योंकि

उन्होंने कभी अल्पमत की सरकार नहीं चलाई है। उन्हें दूसरी उम्मीद यह थी कि एनडीए के घटक लल मोटी के से ज्यादा मंत्रीपद लेने में सफल हो जाएँ। विपक्ष की उम्मीदों के विपरीत कैबिनेट में सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय

अलावा भाजपा के किसी दूसरे नेता को प्रधानमंत्री बनाना पसंद करेंगे। विपक्ष की उम्मीदों के विपरीत मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए और किसी भी घटक दल ने उनको प्रधानमंत्री बनाने का विरोध नहीं किया बल्कि पूरे एनडीए ने उन्हें अपना नेता मान लिया। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विपक्ष में यह उम्मीद पैदा हो गई कि जब सरकार का गठन होगा तो मंत्री पद के लिए एनडीए के घटक दलों में जबरदस्त संघर्ष होगा। उन्हें लगा कि भाजपा कमज़ोर हो गई है तो घटक दल मोदी को ब्लैकमेल करके ज्यादा

जाजपा ने अपने पास रख लिए और विप्रक दलों ने कोई एतराज भी जाहिंगरी किया। विपक्ष को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बहुत उम्मीद थी कि वो मोदी को प्रीवेण्ड नहीं देंगे और सरकार में दखल दंडाजी जैसे रुकावे रखेंगे। सरकार को बने 6 महीने बीमार रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार वैसे ही बदल रही है जैसे पिछले दस सालों में चल रही थी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पुरी तरह से मोदी दे रखने में खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीने जैसे सरकार चली है, उसका रखकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि

मोदी रही है वाली गर के रहा का है कि जाने फ्रिस गई हैं से भरे रहा उकार किन नहीं नहीं बाद गांधी दल मा भाजपा पर जबरदस्त तराक से हमलावर थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब भाजपा पहले से बहुत कमज़ोर हो गई है। शीतकालीन सत्र में तप्पीर बदल चुकी है क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र में बड़ी जीत हासिल करके भाजपा पूरे आत्मविश्वास से संसद में आई है। दूसरी तरफ इन दो राज्यों में मिली करारी हार ने विषय को पस्त कर दिया है। अब विषय में भाजपा से लड़ने का मादा ही नहीं बचा है। अब उसकी प्राथमिकता भाजपा से लड़ने की दिखाई नहीं दे रही है। अब विषय पहले यह फैसला करना चाहता है कि भाजपा से किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ऐसा लग रहा है कि विषयी दलों को यह अहसास हो गया है कि वो राहुल गांधी के नेतृत्व में क नेतृत्व म नाद क मुकाबला कर हा नहीं रहा था। विषय ने राहुल गांधी को कभी अपना नेता नहीं माना है, राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। इंडिया गठबंधन ने पूरे चुनाव के दौरान किसी को अपना नेता नहीं माना था। वास्तव में इंडिया गठबंधन को अपनी जीत पक्की लग रही थी। उसके नेताओं को लग रहा था कि गठबंधन का नेता ही प्रधानमंत्री का स्वाभाविक उम्मीदवार होगा इसलिये वो किसी को नेता मानने को तैयार नहीं हुए। गठबंधन के नेता चाहते थे कि प्रधानमंत्री का फैसला चुनाव परिणाम आने के बाद किया जाए क्योंकि प्रधानमंत्री पद के लिए घटक दलों में चुनाव से पहले ही खींचतान शुरू हो जाती।











